3 मंत्रियों के जिलों के प्रभार में फेरबदल

5 सादगी, संघर्ष और संसदीय मर्यादा के प्रतीक

7 थाना टिमरनी में शांति समिति की बैठक संपन्न



RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 20 प्रति सोमवार, 22 सितंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8


# उपहारों की होड़ में डूबी राजनीति, कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की जनता पर बोझ

**कवर स्टोरी**

-विजया पाठक

एडिटर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उपहार भेंट करने की होड़ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच खुलकर सामने आ गई है। जहां एक तरफ राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारें दिखावटी आयोजनों और निवेश के नाम पर योजनाओं की झड़ी लगा रही हैं। यह होड़ केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गई, बल्कि अब जनता की आर्थिक स्थिति, विकास की प्राथमिकताएँ और शासन की जवाबदेही पर प्रश्नचिंह बन गई है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में 70 वर्षों बाद चीता वापसी को उपहार के रूप में प्रस्तुत कर खुद को विकास का नायक दिखाने का प्रयास किया। इसे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ, स्थानीय रोजगार और पारिस्थितिक संतुलन पर दीर्घकालिक योजना बनाई गई? या यह केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन भर था, जिसका असल लाभ कुछ चुनिंदा पर्यटन व्यापारियों को मिलना तय था?

## केन्द्र सरकार के इर्द-गिर्द घूम रही प्रदेश की राजनीति

### भोपाल का आईटी पार्क इसका सबसे बड़ा प्रमाण

अब डॉ. मोहन यादव ने भी उसी राह पर चलकर पीएम मित्र पार्क को उपहार के तौर पर प्रस्तुत करने की घोषणा की है। इसे बड़े निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थल बताया जा रहा है, जहाँ उद्योगों को स्थापित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जाएगी। लेकिन गहराई से देखें तो यह योजना ऐसे निवेशकों के लिए जमीन होल्ड करने का नया साधन बनती जा रही है, जो कम लागत में भूमि खरीदते हैं और कुछ समय बाद ऊँचे दामों में अन्य व्यापारियों को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। ऐसे उदाहरण प्रदेश में पहले से मौजूद हैं और भोपाल का आईटी पार्क इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आईटी पार्क का सपना एक बड़ी निवेश योजना के रूप में प्रचारित किया गया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद न तो पर्याप्त कंपनियाँ वहाँ स्थापित हुईं और न ही रोजगार के अवसर बढ़े। वहीं दूसरी ओर जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और कुछ निजी निवेशकों ने इसका लाभ उठाकर भारी मुनाफा कमा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि बड़े निवेश के नाम पर बनाई गई योजनाएँ किस तरह आम जनता के हितों से ध्यान हटाकर पूँजीपतियों के लिए अवसर का साधन बन जाती हैं। (शेष पेज 3 पर)

# क्या नए मंत्री मुख्यमंत्री साय की नीतियों और कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे?

## मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक सुलझे और अनुभवी आदिवासी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा से सत्ता संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और जातीय समीकरणों के बीच झूलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्ता संभालने के लगभग डेढ़ वर्ष में दो बार मंत्रीमंडल विस्तार किया है। हाल ही में हुए दूसरे विस्तार में तीन नए विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव को मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई।

राज्यपाल रमन डेका ने राजभवन में शपथ ग्रहण कराई। इस विस्तार के बाद साय कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। प्रश्न यह है कि क्या यह विस्तार सत्ता संतुलन और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है? क्या नए मंत्री टीम साय की नीतियों और कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचा पाएंगे? और सबसे अहम, क्या भाजपा नेतृत्व ने वह गलती नहीं दोहरा दी है, जो पिछली भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में की थी? (शेष पेज 2 पर)

# आज भारत को चाहिए वैश्विक पटल पर एक सशक्त और अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता

## कमलनाथ को मिलनी चाहिए अटल बिहारी जी जैसी जिम्मेदारी

-विजया पाठक

विश्व सहित भारत आज एक जटिल और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे- नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का वातावरण है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत को न केवल अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा करनी है, बल्कि एक



स्थिर और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को और भी मजबूत करना है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के अनुभव और दूरदर्शी सोच का लाभ उठाना देश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने वाणिज्य और उद्योग के रूप में पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाये। (शेष पेज 2 पर)

# क्या मोदी सरकार को कमलनाथ के अनुभवों और पड़ोसी देशों से संबंधों का लाभ लेना चाहिए?

(पेज 1 का शेष)

अब इस स्तर का कोई कूटनीतिज्ञ व्यक्ति नही है। भारत की संप्रभुता के हिसाब से इन सीमावर्ती देशों को अपने पक्ष में करके रखना और इनके हालातों को भी अपने पक्ष में रखने के लिये रीति और नीति की जो आवश्योकता है, वो कमलनाथ में देखने को मिलती है। यहां सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार इनके अनुभव और संबंधों का लाभ लेकर कमलनाथ को यह जिम्मेदारी दे सकती है।

## राजीव गांधी ने किया था ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन

भारतीय राजनीति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की एक गौरवशाली परंपरा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। यह इस बात का प्रमाण है कि जब देश की संप्रभुता और सम्मान की बात आती है, तो सभी राजनीतिक मतभेद भुला दिए जाते हैं। आज वर्तमान में केंद्र सरकार भी इसी परंपरा का निर्वहन कर सकती है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमलनाथ के अनुभव का लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं और उन्हें पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने या अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के पक्ष को मजबूती से रखने की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो इसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

## कमलनाथ, एक वैश्विक नेता और कुशल वार्ताकार

कमलनाथ का राजनीतिक जीवन केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का मजबूती से प्रतिनिधित्व किया है। विशेष रूप से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारत की विदेश व्यापार नीति और वैश्विक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला था। यह कमलनाथ का ही कुशल नेतृत्व था कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) की जटिल वार्ताओं में भारत ने विकासशील देशों के हितों का एक मजबूत पैरोकार बनकर उभरा। उन्होंने विकसित देशों के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और भारत के किसानों, छोटे उद्योगों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े रहे। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि विकासशील देशों में गरीबी और असमानता को दूर करना भी होना चाहिए। उनके इसी दृढ़ संकल्प ने उन्हें विकासशील देशों का एक सर्वमान्य नेता बना दिया।

आंकड़ों पर नजर डालें तो, कमलनाथ के कार्यकाल में भारत के विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2004-05 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% से अधिक की वृद्धि थी। उन्होंने "इंडिया एवरी वेयर" जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक निवेशकों का भारत पर विश्वास बढ़ा और देश में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई। यह उनकी ही दूरदृष्टि थी कि उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की नीति को आगे बढ़ाया, जिसने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की नींव रखी।

## पड़ोसी देशों में अस्थिरता और कमलनाथ की प्रासंगिकता

आज जब हमारे पड़ोसी देशों की आंतरिक कलह और अस्थिरता से जूझ रहे हैं तो इसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पड़ना स्वाभाविक है। इन देशों के साथ संबंधों में संतुलन और मजबूती बनाए रखना भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में, कमलनाथ जैसा अनुभवी नेता एक संकटमोचक की भूमिका निभा सकता है। उनका दशकों का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव, विभिन्न देशों के नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कूटनीति की गहरी समझ उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बनाती है। केन्द्रीय मंत्री रहते हुए उन्हों ने कई देशों की यात्राएं की और भारत का प्रतिनिधित्व किया। व्यापारिक और सामरिक विषयों पर कमलनाथ ने मजबूती से देश का पक्ष रखा। जिसका नतीजा यह रहा कि भारत पर कभी भी व्यापार को लेकर अड़चनें नहीं आयीं जैसी आज आ रही हैं। वह चाहे अमेरिका रहा हो या हमारे पड़ोसी देश। व्यापारिक रिश्तों के चलते हितों के परिप्रेक्ष्य में भारत हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। कमलनाथ का विजन था कि इन देशों से व्यापारिक रिश्ते बेहतर बने ताकि वह देश भारत से दबे भी रहे और व्यापार में आश्रित भी रहें। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विककरण से भारत के कारोबारों को मजबूत करना, उनकी नीति थी। जैसे- श्रीलंका से चाय और मसाले, नेपाल के युवाओं की गोरखा रेजिमेंट को बढ़ावा देना। ऐसे देशों के लिये कमलनाथ का विजन फायदेमंद रहा। पड़ोसी देशों के बीच व्यापार के साथ आत्मीय जुड़ाव भी बरकरार रहा।

कमलनाथ केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टेट्समैन हैं, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बुलंद किया है। उनका ज्ञान, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ उन्हें एक परिपक्व राजनेता बनाता है। आज की विषम परिस्थितियों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके अनुभव का लाभ लेना न केवल भारत के पड़ोसी देशों में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होगा, बल्कि यह विश्व पटल पर भारत की संप्रभुता को और भी सुदृढ़ करेगा। यह एक ऐसा कदम होगा जो राष्ट्रहित में एक नया और सुनहरा अध्याय लिखेगा।

# क्या नए मंत्री मुख्यमंत्री साय की नीतियों और कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे?

(पेज 1 का शेष)

## विस्तार की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

साय सरकार को सत्ता में आए अब तक का समय अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इस अवधि में जनता की उम्मीदें बड़ी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक सुलझे और अनुभवी आदिवासी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती है एक ओर शासन-प्रशासन को गति देना और दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती के साथ भाजपा को अगले चुनाव में जीत की दिशा में ले जाना। इसी पृष्ठभूमि में मंत्रीमंडल विस्तार का महत्व बढ़ जाता है। कैबिनेट केवल विभागों का बँटवारा भर नहीं होता, बल्कि यह सरकार के राजनीतिक संदेश और रणनीति का आईना होता है।

## नए मंत्रियों की जिम्मेदारियाँ

साय सरकार ने तीन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अनुभव और युवाशक्ति दोनों का संतुलन साधना चाहती है। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि एवं विधायी कार्य जैसे अहम विभाग मिले हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी पर अंकुश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना आज के समय की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। यादव से अपेक्षा है कि वे इन विभागों में ठोस सुधारात्मक कदम उठाएँ। खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के साथ अनुसूचित जाति विकास की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, यह विभाग सबसे अहम है। यदि वे कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर गंभीरता से कार्य करते हैं, तो सरकार की साख बढ़ेगी। राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन की असीम संभावनाओं वाला राज्य है, किंतु अब तक यह क्षेत्र अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाया। अग्रवाल के सामने यह अवसर है कि वे राज्य को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दें।

## समीकरण साधने की राजनीति

साय सरकार के इस विस्तार में राजनीतिक समीकरणों को साधने की झलक साफ दिखती है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया गया है। भाजपा जानती है कि चुनाव से पहले संगठन और सत्ता दोनों को संतुलित रखना अनिवार्य है। हालांकि, यही वह बिंदु है जहाँ पिछली भूपेश बघेल सरकार ने गलती की थी। कांग्रेस आलाकमान ने सत्ता संतुलन और गुटबाजी पर इतना ध्यान दिया कि शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई। नतीजा यह रहा कि जनता में असंतोष पनपा और भाजपा सत्ता में लौट आई। साय सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वह समीकरण साधने की राजनीति में उलझकर प्रशासनिक दक्षता और विकास की गति को धीमा न होने दे।

## जनता की अपेक्षाएँ और मंत्रीमंडल की परीक्षा

छत्तीसगढ़ की जनता विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर परिणाम चाहती है। चुनावी वादों और घोषणाओं से अधिक अब वह कामकाज और उपलब्धियों को तौल रही है। साय सरकार ने जब तीन नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, तो जनता यह देखेगी कि वे अपने विभागों में कितनी पारदर्शिता, सक्रियता और नवाचार लाते हैं। शिक्षा विभाग को डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण बनाने की चुनौती है। कौशल विकास विभाग को युवाओं को वास्तविक रोजगार से जोड़ने की जरूरत है, न कि केवल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बाँटने की। पर्यटन विभाग को राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने का काम करना होगा। यदि मंत्री केवल औपचारिकताओं में उलझे रहे, तो यह विस्तार जनता के लिए निराशा का कारण भी बन सकता है।

## समीक्षा और जवाबदेही की आवश्यकता

राजनीति का इतिहास बताता है कि केवल मंत्रीमंडल विस्तार से सरकार की छवि नहीं बदलती। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब मंत्री अपने विभागों में ठोस काम करें और उसकी प्रगति जनता तक पहुँचे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए यह जरूरी है कि वे समय-समय पर मंत्रियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट माँगें। विभागीय कामकाज की समीक्षा करें और जनता के बीच उसकी जानकारी साझा करें। यदि मंत्री अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते, तो फेरबदल करने में संकोच न करें। यही वह बिंदु है जहाँ भाजपा नेतृत्व कांग्रेस से सबक ले सकता है। कांग्रेस ने समय रहते अपने मंत्रियों की समीक्षा नहीं की, जिसके कारण असंतोष और अव्यवस्था बढ़ी। यदि साय सरकार समय रहते सक्रिय कदम उठाती है, तो इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। साय सरकार के पास अभी समय है। अगले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले यह कैबिनेट सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का चेहरा बनेगा। यदि मंत्री अपने-अपने विभागों में उल्लेखनीय काम कर पाए, तो भाजपा को चुनावी लाभ मिलेगा।

# मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया मंत्रियों के जिलों के प्रभार में फेरबदल

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा को 04 जिलों का प्रभार दिया गया है। खुशवंत साहेब को सक्ती, गजेंद्र यादव को राजनांदगांव और राजेश अग्रवाल को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में साय मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद नये मंत्रियों गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल को जिलों की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ ही प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार भी बदल गया है। राज्य सरकार ने नये मंत्रियों को प्रभारी बनाते हुए आदेश जारी कर दिया हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को चार जिलों दुर्ग, बालोद, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चाकी और बस्तर का प्रभारी बनाया गया है। बताया जाता है कि बस्तर माओवादी हिंसा प्रभावित इलाका होने के कारण विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार-भाटापारा, महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को सक्ती, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव और पर्यटन व संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले का प्रभार सौंपा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जासवाल ने छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर को आने वाले समय में शून्य करने का लक्ष्य है। देश में 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां से ही संपूर्ण सृष्टि का आधार होता है। ऐसे में प्रसव के दौरान किसी की मौत सभी के लिए दुख की बात होती है। राज्य गठन के समय मातृ मृत्यु की दर 365 थी, जो वर्तमान में 141 और शिशु मृत्यु दर 79 से 38 हो चुकी है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही स्वस्थ भारत बनेगा। साथ ही देश को विकसित बनाने में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होगी। स्वास्थ्य सेवाएं संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि अभियान के माध्यम से न केवल माताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है, बल्कि प्रदेश के उन 30 विकासखंडों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है।

# छत्तीसगढ़ में 1.84 लाख श्रमिकों को 65 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान

-दुगेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राज्य के 1.84 लाख श्रमिकों को 65 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमवीरों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ एवं विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों के परिश्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि श्रमवीरों के उत्साह और भागीदारी से प्रदेशवासियों के सपने पूरे होंगे। इस अवसर पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के मेहनतकश श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की कि दीदी ई-रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही, पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का संपूर्ण खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनहितैषी कार्यों से प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ''छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर हम सभी श्रमवीरों के परिश्रम को नमन करते हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है- चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा हो या आवास और औजारों की सुविधा, सरकार हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ी है।

## खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक लाख 84 हजार 220 श्रमिकों के खातों में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि के अंतर्गत 65 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। उन्होंने कहा, ''पारदर्शिता हमारी सरकार की पहचान है। किसानों और श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। अब अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर भी एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।

# बेलगाम दौड़ते वाहन या काल

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले में प्रतिदिन औसत 2 या 3 दुर्घटनाओं का समाचार मिलता है। सोशल मीडिया या दैनिक समाचार पत्र द्वारा वाहन दुर्घटनाओं मे मौत की खबर प्रमुख रूप से देख रहे हैं। आखिर जिले में सड़क दुर्घटनाओं थमने का नाम क्यों नही ले रहीं हैं, सड़कों पर बेलगाम दोडते वाहन जब चाहे निर्दोषों के लिए काल बन जाते हैं, लेकिन इन पर सख्ती से कार्यवाही न किए जाने से ऐसी दर्दनाक घटनाएँ थमने का नाम नही ले रहीं हैं। इस समय दो पहिया वाहन चालकों के लिए निर्देशित किया गया है कि बिना हेल्मेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ना दिया जावे, यह शर्त या नियम बहुत ही अच्छा हैं, लेकिन क्या वाहन चालकों के लिए वाहन चलाते हुए हेल्मेट जरूरी है या सिर्फ पेट्रोल के लिए हेल्मेट जरूरी हैं, यहीं फरमान समझ से परे हैं।

सड़क हादसे चिंताजनकः जिला में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों का ग्राफ चिंताजनक है, नरसिंहपुर की सड़कों पर भयाभय सड़क हादसे के बाद यातायात कर्मियों को वाहन चलान काटने के आलावा यातायात नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि यातायात विभाग अमला वाहनों की गति नियंत्रण करने में गंभीरता दिखलाए तो सड़क हादसों में स्वतः ही कमि आ जाएगी।

# उपहारों की होड़: कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की जनता पर बोझ

(पेज 1 का शेष)

## संसाधनों का दोहन करने की नीति उजागर

राज्य पर 04 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझती जनता के बीच इस कर्ज का बोझ प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा रहा है। ऐसे में हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को उपहार के रूप में दिखाकर जनता का ध्यान भटकाना क्या उचित है? क्या इन योजनाओं की प्राथमिकता जनता की जरूरतों के आधार पर तय हो रही है या राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में? पीएम मित्र पार्क जैसी योजनाएँ, जो बड़े निवेशकों के लिए जमीन होल्ड करने का नया माध्यम बनती जा रही हैं, जनता के संसाधनों का दोहन करने की नीति को उजागर करती हैं। कम पैसों में भूमि खरीदकर उसे ऊँचे दामों में बेचने का खेल प्रदेश की आर्थिक असमानता को और गहरा करता है। इससे न तो स्थानीय उद्योगों का विकास होता है, न ही युवाओं को रोजगार मिलता है। उल्टा, भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें छिनती हैं और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता।

## निवेश का बड़ा हिस्सा योजनाओं की दिखावटी सफलता में खर्च हो रहा

सवाल यह भी उठता है कि क्या इन योजनाओं में पारदर्शिता है? क्या निवेशकों की जाँच-पड़ताल, परियोजना की दीर्घकालिक योजना और सामाजिक लाभ का आकलन सार्वजनिक किया गया है? यदि नहीं, तो यह योजनाएँ केवल कागजों में निवेश दिखाकर जनता से भरोसा तोड़ने का माध्यम बन रही हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उपहारों की यह होड़ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। विकास का अर्थ बड़े-बड़े पार्कों, महंगे समारोहों और राजनीतिक ब्रांडिंग से नहीं है। विकास वह है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करे, उद्योगों को रोजगार से जोड़े और किसानों व छोटे व्यापारियों की मदद करे। दुर्भाग्यवश, वर्तमान योजनाओं में यही बुनियादी लक्ष्य गौण होते जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि योजनाओं के माध्यम से धन का उपयोग किस दिशा में हो रहा है। जहाँ राज्य की वित्तीय स्थिति डगमगा रही है, वहीं निवेश का बड़ा हिस्सा योजनाओं की दिखावटी सफलता में खर्च हो रहा है। जनता के कर से एकत्रित धन का उपयोग ऐसे कार्यक्रमों में करना, जिनका लाभ चुनिंदा वर्गों तक सीमित रह जाए, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता।

## निवेश का बड़ा हिस्सा योजनाओं की दिखावटी सफलता में खर्च हो रहा

इस पूरे परिदृश्य में आवश्यक है कि राज्य सरकारें योजनाओं को केवल उपहार या राजनीतिक प्रचार के रूप में न प्रस्तुत करें, बल्कि आर्थिक स्थिति का गंभीरता से विश्लेषण कर जनहित को केंद्र में रखकर प्राथमिकताएँ तय करें। विकास का वास्तविक अर्थ जनता की भागीदारी, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। यदि योजनाएँ केवल निवेशकों के लिए जमीन होल्ड करने का साधन बनती रहीं तो यह प्रदेश के आर्थिक भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगी। समय आ गया है कि जनता, मीडिया और नीति निर्धारक मिलकर यह सवाल उठाएँ कि क्या ये योजनाएँ वास्तव में विकास ला रही हैं या केवल राजनीतिक लोकप्रियता और आर्थिक शोषण का खेल हैं। उपहार की राजनीति से आगे बढ़कर जनहित की राजनीति का समय आ चुका है। वरना, कर्ज और असमानता की खाई दिन-ब-दिन और गहरी होती जाएगी।

# सम्पादकीय

## जीएसटी की नई दरें और आमजन की राहत : कितनी सच्चाई, कितनी उम्मीद

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद से ही समय-समय पर इसकी दरों में बदलाव किए जाते रहे हैं। सरकार का तर्क हमेशा रहा है कि जीएसटी दरों को यथासंभव सरल और जनसुलभ बनाया जाए, ताकि इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। हाल ही में घोषित नई दरों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आमजन को आखिरकार इससे कितनी राहत मिल पाएगी। क्या यह बदलाव वाकई उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालने वाला है या फिर यह केवल सांकेतिक रियायत भर है? नई दरों का सबसे बड़ा आकर्षण उन वस्तुओं और सेवाओं पर कर की कमी है, जिनका सीधा संबंध आमजन के दैनिक जीवन से है। सामान्य उपभोक्ता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही रहती है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं खाद्य पदार्थ, घरेलू सामान, कपड़े और दवाइयों पर टैक्स कम हो। जब इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटती हैं, तो उपभोक्ता को तत्काल राहत का अनुभव होता है।

उदाहरण के तौर पर, यदि तैयार खाद्य पदार्थों या पैकेज्ड दवाइयों पर कर की दर कम की गई है, तो इससे उपभोक्ता को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को भी दरों में राहत से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है, जो अंततः उपभोक्ता को सस्ती सेवाओं के रूप में प्राप्त होगी। दरअसल, जीएसटी दरों में कमी केवल उपभोक्ता के लिए ही राहत नहीं है, बल्कि यह छोटे और मध्यम व्यापारियों की भी सहूलियत है। जब कर ढांचा सरल होता है और दरें कम होती हैं, तो कर चोरी की प्रवृत्ति घटती है। इसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता को वास्तविक दर पर वस्तु और सेवा प्राप्त होती है।

फिर भी, सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि दरों में कमी का लाभ वास्तव में उपभोक्ता तक पहुंचे। कई बार व्यापारी कम कर का फायदा खुद रख लेते हैं और कीमतें घटाने में देर करते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह निगरानी तंत्र मजबूत करे और यह सुनिश्चित करे कि राहत जनता तक पहुँचे। देश में महँगाई दर लगातार आमजन की चिंता का विषय रही है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। यदि नई जीएसटी दरों से दैनिक जीवन की जरूरतों पर कर बोझ कम होता है, तो निश्चित रूप से महँगाई पर अंकुश लगेगा। हालांकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि वस्तुओं की कीमत केवल कर पर ही निर्भर नहीं करती। उत्पादन लागत, कच्चे माल की उपलब्धता, ईंधन के दाम और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जीएसटी दरों में बदलाव अकेले महँगाई पर नियंत्रण की गारंटी नहीं है। जीएसटी दरों में हर कमी का सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ता है। राजस्व में कमी का अर्थ है कि सरकार को विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। यही कारण है कि सरकार दरों में कटौती सोच-समझकर करती है। फिर भी, जब कर की दरें ज्यादा होती हैं तो उपभोक्ता पर बोझ बढ़ता है और बाजार में मंदी का माहौल बनता है। जबकि कर में रियायत से खपत बढ़ती है और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व की भरपाई हो जाती है। यही कारण है कि नई दरों से उपभोक्ता राहत और सरकार को दीर्घकालिक लाभ, दोनों की उम्मीद की जा रही है।

# सियासी गहमागहमी

### भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज, एक अधूरी कहानी

भाजपा ने देश में चाँद पर पहुंचने से लेकर चाय बेचने तक के किस्से गढ़ डाले, लेकिन अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करने में असफल है। शायद यह वही रहस्य है, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिकों को "इसरो" नहीं, बल्कि "ज्योतिषी सम्मेलन" बुलाना पड़ेगा। पार्टी दफ्तर में चर्चा गर्म है कि नाम तय हो चुका है, बस घोषणा का मुहूर्त नहीं मिल रहा। कोई कहता है कि शनि की टेढ़ी नजर हटे तो अध्यक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है कि नेता जी की कुंडली में "अध्यक्ष योग" कमजोर है। कुछ कार्यकर्ता मानते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी अब "म्यूजियम पीस" बन चुकी है। सब उसे देखते हैं, छूते हैं, लेकिन उस पर बैठने का साहस कोई नहीं करता। एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह दिया कि "कुर्सी ढूंढना आसान है, लेकिन उसे स्थायी करना अब असंभव।" असलियत यह है कि पार्टी में इतनी लंबी कतार है कि चुनाव आयोग भी हार मान जाए। हर कोई चाहता है कि घोषणा देर से हो, ताकि उम्मीद जिंदा रहे। इसीलिए भाजपा अध्यक्ष का नाम अब एक राजनीतिक "सस्पेंस थ्रिलर" बन चुका है। जनता बेचैन है कि नया अध्यक्ष कब आएगा, लेकिन शायद भाजपा मानती है कि सस्पेंस ही सबसे बड़ा प्रचार है। और भाई, जब चुनावी राजनीति में हर चीज मार्केटिंग है, तो अध्यक्ष का नाम घोषित करने की क्या जल्दी?

### भूपेश बघेल के काले कारनामे पर्दा उठेगा या फिर नया पर्दा डाला जाएगा?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक और काले कारनामे से जल्द पर्दा उठने वाला है। ऐसा दावा करने वाले राजनीतिक गलियारों में मानो "पर्दानशीं ड्रामा" चल रहा हो। लेकिन जनता हैरान है कि आखिर कितने पर्दे हैं? पिछले पाँच सालों में तो इतने पर्दे उठे कि अगर उन्हें जोड़ दिया जाए, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तंबू पंडाल तैयार हो जाए। कहा जा रहा है कि इस बार पर्दा उठेगा तो सच का सूरज चमकेगा। लेकिन जनता को डर है कि सूरज से पहले फिर धुंध ही निकलेगी। आखिर राजनीति में काला कारनामा अब कोई अपवाद नहीं रहा, बल्कि यह तो नेताओं की "योग्यता प्रमाणपत्र" जैसा बन गया है। बघेल समर्थकों का कहना है कि यह सब विपक्ष की साजिश है मतलब, उनकी नजर में हर पर्दे के पीछे विपक्ष ही है। विपक्ष का तर्क है कि बघेल के पर्दों के नीचे छुपे खजाने की गिनती गूगल कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। असलियत चाहे जो भी हो, जनता को अब इन पर्दा-कथाओं से उतनी ही थकान हो रही है, जितनी हर महीने बिजली बिल देखकर होती है। सवाल बस इतना है कि अगला पर्दा उठेगा तो सच सामने आएगा, या फिर कोई नया डिजाइनर पर्दा टाँग दिया जाएगा।

## हफ्ते का कार्टून

## ट्वीट-ट्वीट

सुबह 4 बजे उठो,
36 सेकंड में 2 वोटर भिटाओ,
फिर सो जाओ - ऐसे भी हुई वोट चोरी!

पुलाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश खाद संकट में देश का अव्वल राज्य बनता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए परेशान किसानों में आपसी मारपीट की खबरें भी सामने आने लगी हैं। अगर ध्यान से देखें तो पिछले दो महीनों में प्रदेश के हर इलाके से खाद की किल्लत के समाचार आए हैं। किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा है, कई जगहों पर किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठियां चलायीं, कई जगह किसान बेहोश होकर गिर पड़े और बहुत सी जगहों पर नकली खाद मिलने के भी समाचार सामने आए हैं।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

## राजवीरों की बात

# सोमनाथ चटर्जी : सादगी, संघर्ष और संसदीय मर्यादा के प्रतीक

समता पाठक/जगत प्रवाह

सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के उन विरल व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सादगी और संसदीय परंपराओं के पालन की मिसाल कायम की। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता रहे और 2004 से 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को अपनी निष्पक्षता और मर्यादा के साथ प्रतिष्ठित किया। उनका जीवन संघर्ष, विद्वता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण से भरा रहा। सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था। उनके पिता निर्मल चंद्र चटर्जी प्रख्यात वकील और हिन्दू महासभा के नेता थे। उनकी माता बिनापानी देवी धार्मिक और संस्कारवान महिला थीं। राजनीतिक वातावरण से घिरे होने के कारण सोमनाथ का बचपन से ही राजनीति और सामाजिक मुद्दों की ओर झुकाव रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। इसके बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के समय ही उनमें समाजवादी और वामपंथी विचारों के प्रति झुकाव विकसित हुआ।

सोमनाथ चटर्जी ने वकालत से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही राजनीति की ओर रुख किया। वे 1968 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े। 1971 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुँचे। यह उनकी लंबी संसदीय यात्रा का आरंभ था। चटर्जी कुल मिलाकर दस बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे 1971 से 2008 तक सक्रिय रूप से राजनीति में बने रहे। संसद में उनका व्यक्तित्व एक विद्वान और सशक्त वक्ता के रूप में उभरा। उनकी तार्किकता, मुद्दों पर गहन समझ और सधी हुई भाषा ने उन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में सम्मान दिलाया।

सोमनाथ चटर्जी का संसदीय जीवन अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। वे कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उनकी पहचान केवल वामपंथी विचारधारा के नेता के रूप में नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने वाले जननायक के रूप में हुई। वे सदैव मानते थे कि संसद जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक सांसद का दायित्व है। अपने भाषणों में वे हमेशा तथ्यों और तर्कों पर जोर देते थे। वर्ष 2004 में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार सत्ता में आई, तब सोमनाथ चटर्जी को सर्वसम्मति से 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के बीच निष्पक्षता से कार्य किया। वे सख्त लेकिन न्यायसंगत अध्यक्ष माने जाते थे। संसदीय शिष्टाचार, अनुशासन और लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनके कार्यकाल में प्रश्नकाल की गुणवत्ता और संसद की कार्यवाही की गरिमा में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। उन्होंने सांसदों को समय पर सदन में उपस्थित रहने, सारगर्भित बहस करने और जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाने के लिए प्रेरित किया। सोमनाथ चटर्जी का नाम भारतीय संसदीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्हें उनकी विद्वता और निष्पक्षता के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक परंपराओं पर कई लेख और भाषण दिए, जो आज भी मार्गदर्शक माने जाते हैं।

## "माँ का आह्वान : महाशक्ति से साक्षात्कार का समय"

# शारदीय नवरात्रि : आस्था, ऊर्जा और आत्म-उत्थान का महापर्व

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

हवा में एक नई ऊर्जा घुलने लगी है, वातावरण में एक आध्यात्मिक स्पंदन महसूस हो रहा है। यह संकेत है कि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। नौ दिनों तक चलने वाला दिव्य उत्सव, जो केवल उपवास, पूजा और गरबे तक सीमित नहीं, बल्कि यह हम सभी के लिए एक वार्षिक आमंत्रण है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ठहरकर, अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानने का, जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। इस पावन उत्सव पर, आइए इस बार केवल उपवास ही नहीं, बल्कि अपने भीतर आत्म-जागरण का भी प्रण लें।

यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे अंदर की वह चेतना है, जो सही समय पर जागृत हो जाए तो असंभव को भी संभव बना देती है। जब हम आदिशक्ति को नमन करते हैं, तो हम उस मूल ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ। आज जब दुनिया अनिश्चितताओं और तनाव से जूझ रही है, तो यह उपासना हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। माँ की शक्ति हमें पोषण भी देती है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे भीतर भी सृजन और संहार, दोनों की शक्ति निहित है, सृजन सकारात्मक विचारों का और संहार अपनी नकारात्मकता का।

### नौ दिन, नौ संकल्पः

आने वाले नवदुर्गा के नौ रूप केवल देवी की मूर्तियाँ नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाले नौ शक्तिशाली सूत्र हैं। आइए, इस नवरात्रि में हर दिन एक देवी के गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेने की तैयारी करें:

**पहले दिन का संकल्प** - माँ शैलपुत्री (अडिग विश्वास) : पर्वतराज की पुत्री की तरह अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर चट्टान की तरह अडिग बनें। प्रण लें कि आने वाले दिनों में छोटी-मोटी बाधाओं से विचलित नहीं होंगे।

**दूसरे दिन का संकल्प** - माँ ब्रह्मचारिणी (अनुशासन) : तप और संयम की देवी हमें सिखाती हैं कि महान चीजें अनुशासन से ही हासिल होती हैं। तय करें कि इस नवरात्रि कोई एक बुरी आदत छोड़ेंगे या एक अच्छी आदत को जीवन में शामिल करेंगे।

**तीसरे दिन का संकल्प** - माँ चंद्रघंटा (निर्भयता) : यह रूप हमें डर पर विजय पाना सिखाता है। उस एक डर का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है।

**चौथे**

**दिन का संकल्प** - माँ कूष्मांडा (सकारात्मकता) : अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी से प्रेरणा लें। प्रण करें कि इन नौ दिनों में किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में घर नहीं करने देंगे।

**पांचवें दिन का संकल्प** - माँ स्कंदमाता (करुणा) : मातृत्व की यह देवी हमें प्रेम और करुणा की शक्ति सिखाती हैं। संकल्प लें कि आप किसी एक व्यक्ति की निस्स्वार्थ मदद अवश्य करेंगे।

**छठे दिन का संकल्प** - माँ कात्यायनी (न्याय) : अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली यह वीरांगना हमें सिखाती है कि चुप रहना भी एक अपराध है। जहाँ भी कुछ गलत देखें, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का साहस जुटाएं।

**सातवें दिन का संकल्प** - माँ कालरात्रि (अंधकार पर विजय) : यह प्रचंड रूप हमें सिखाता है कि सबसे घने अंधकार के बाद ही सुबह होती है। जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं।

**आठवें दिन का संकल्प** - माँ महागौरी (आत्मशुद्धि) : यह शांत और निर्मल रूप आंतरिक शांति का प्रतीक है। प्रण लें कि आप क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष से खुद को दूर रखेंगे और मन को शांत रखने का अभ्यास करेंगे।

**नौवें दिन का संकल्प** - माँ सिद्धिदात्री (क्षमता पर विश्वास) : सभी सिद्धियों को देने वाली माँ हमें हमारी अनंत क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती हैं। अपने सबसे बड़े सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए खुद को प्रेरित करें।

### आराधना का असली अर्थः उपवास से ऊपर उठकर

याद रखें, नवरात्रि का व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों, आदतों और शब्दों का त्याग है। असली पूजा थाली सजाना नहीं, किसी की जिंदगी में उम्मीद का दीया जलाना है। जब हम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, या प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी हम माँ शक्ति की सबसे सच्ची आराधना करते हैं।

उत्सव मनाएं और एक बेहतर इंसान बनें तो आइए, इस नवरात्रि को केवल एक परंपरा की तरह मनाने की जगह, इसे अपने जीवन का एक "ट्रांसफॉर्मेशनल फेस्टिवल" बनाने का संकल्प लें। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का और उसे दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का। अब से जब आप "जय माता दी" कहें, तो यह सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि आपके भीतर की उस दिव्य शक्ति का उद्घोष हो जो आपको और इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है। यही सच्ची आराधना है और यही आत्म-विजय का असली उत्सव है।

## असम में घुसपैठ और बदलती जनसांख्यिकी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान-

# अनुत्तरित सवाल है सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ

-प्रमोद भार्गव

अनुत्तरित सवालों को नए ढंग से राजनीतिक मुद्दों में बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विलक्षण शैली रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा-370, 35-ए, तीन तलाक और राम मंदिर जैसे आजादी के बाद से अनुत्तरित चले आ रहे प्रश्नों के समाधान के बाद मोदी ने असम की धरती से घुसपैठ करने और कराने वालों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की मदद से जनसांख्यिकीय घनत्व बदलने की साजिश चल रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हमारी सरकार घुसपैठियों को देश के साधन-संसाधन पर कब्जा नहीं करने देगी। घुसपैठियों को मदद देने वालों को सीधी चुनौती देते हुए मोदी ने कहा, 'घुसपैठियों को हटाने में हम अपना जीवन लगा देंगे। घुसपैठियों को पनाह देने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब इन्हें संरक्षण देती रही, जिससे घुसपैठिए हमेशा भारत में बस जाएं और भारत का राजनीतिक भविष्य तय करें। कांग्रेस के लिए देशहित से बड़ा, अपने वोट-बैंक का हित रहा है। किंतु अब यह नहीं चलेगा।

> **बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बक्सा, चिरांग, धुबरी और कोकराझार जिलों में सबसे ज्यादा है। इन्हीं जिलों में बोडो आदिवासी हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं। लिहाजा बोडो और मुस्लिमों के बीच रह-रहकर हिंसक वारदातें होती रही हैं। पिछले 18 साल में ही हिंसा की 15 बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिनमें 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।**

बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला एक बड़ी समस्या बन गया है। जो यहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है। असम के लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेश म्यांमार से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके आए मुस्लिमों ने उनके न केवल आजीविका के संसाधनों को हथिया लिया है, बल्कि कृषि भूमि पर भी काबिज हो गए हैं। इस कारण राज्य का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है। लिहाजा यहां के मूल निवासी बोडो आदिवासी और घुसपैठियों के बीच जानलेवा हिंसक झड़पें भी होती रहती हैं। नतीजतन अवैध और स्थाई नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता पत्रक बनाने की पहल हुई। इस निर्देश के मुताबिक 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को मूल नागरिक माना गया है। इसके बाद के लोगों को अवैध नागरिकों की सूची में दर्ज किया गया है। इस सूची के अनुसार 3.29 करोड़ नागरिकों में से 2.89 करोड़ लोगों के पास नागरिकता के वैध दस्तावेज हैं। शेष रह गए 40 लाख लोग फिलहाल अवैध नागरिकों की श्रेणी में रखे गए हैं। इस तरह के संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल घुसपैठिए अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो यह उन राजनीतिक दलों को वजूद बचाए रखने की दृष्टि से खतरे की घंटी है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ को बढ़ावा देकर अवैध नागरिकता को वैधता देने के उपाय करते रहे हैं।

असम में अवैध घुसपैठ का मामला नया नहीं है। 1951 से 1971 के बीच राज्य में मतदाताओं की संख्या अचानक 51 प्रतिशत बढ़ गई। 1971 से 1991 के बीच यह संख्या बढ़कर 89 फीसदी हो गई। 1991 से 2011 के बीच मतदाताओं की तादात 53 प्रतिशत बढ़ी। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से यह भी देखने में आया कि असम में हिंदू आबादी तेजी से घटी है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी और तेजी से बढ़ी। 2001 में जहां यह बढ़ोत्तरी 30.9 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गई। जबकि देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोत्तरी 13.4 प्रतिशत से 14.2 फीसदी तक ही हुई। असम में 35 प्रतिशत से अधिक मुस्लिमों वाली 2001 में विधानसभा सीटें 36 थी, जो 2011 में बढ़कर 39 हो गईं। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से 1991 तक हिंदुओं की जनसंख्या में 41.89 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में 77.42 फीसदी की बेलगाम वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच असम में हिंदुओं की जनसंख्या 14.95 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मुस्लिमों की 29.3 फीसदी बढ़ी। इस घुसपैठ के कारण असम में जनसंख्यात्मक घनत्व गड़बड़ा गया और सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बोडो आदिवासियों ने भुगता। इसी के दुष्फल स्वरूप कई बोडो उग्रवादी संगठन अस्तित्व में आ गए।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बक्सा, चिरांग, धुबरी और कोकराझार जिलों में सबसे ज्यादा है। इन्हीं जिलों में बोडो आदिवासी हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं। लिहाजा बोडो और मुस्लिमों के बीच रह-रहकर हिंसक वारदातें होती रही हैं। पिछले 18 साल में ही हिंसा की 15 बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिनमें 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। घटनाएं घटने के बावजूद इस हिंसा का संतोषजनक पहलू यह रहा है कि हिंसा के मूल में हिंदू, ईसाई, बोडो आदिवासी और आजादी के पहले से रह रहे पुश्तैनी मुसलमान नहीं हैं। विवाद की जड़ में स्थानीय आदिवासी और घुसपैठी मुसलमान हैं।

इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने के काम में असम राज्य कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी भूमिका रही है। घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेसियों ने इन्हें बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड तक हासिल कराए। नागरिकता दिलाने की इसी पहल के चलते घुसपैठिए कांग्रेस को झोली भर-भर के वोट देते रहे हैं। कांग्रेस की तरुण गोगाई सरकार इसी बूते 15 साल सत्ता में रही। लेकिन लगातार घुसपैठ ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी थी। फलस्वरूप भाजपा सत्ता में आ गई। इस अवैध घुसपैठ के दुष्प्रभाव पहले अलगाववाद के रूप में देखने में आ रहे थे, लेकिन बाद में राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में बदल गए। इन दुष्प्रभावों को पूर्व में सत्तारूढ़ रहा कांग्रेस का केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व जानबूझकर वोट बैंक बनाए रखने की दृष्टि से अनदेखा करता रहा है। लिहाजा धुबरी जिले से सटी बांग्लादेश की जो 134 किलोमीटर लंबी सीमा-रेखा है उस पर कोई चौकसी नहीं है। नतीजतन घुसपैठ आसानी से जारी है। असम को बांग्लादेश से अलग ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इस नदी का पाट इतना चौड़ा और दलदली है कि इस पर बाड़ लगाना या दीवार बनाना नामुमकिन है। केवल नावों पर सशस्त्र पहरेदारी के जरिए घुसपैठ को रोका जाता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा के घुसपैठियों के विरुद्ध कड़े रुख के चलते इनकी वापसी भी शुरू हुई है।

दरअसल 1971 से ही एक सुनियोजित योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, बिहार और दूसरे प्रांतों में घुसपैठ का सिलसिला जारी है। म्यांमार से आए 60,000 घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम भी कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद में गलत तरीकों से भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं। जबकि कश्मीर से हिंदू, सिख और बौद्धों को धकिया कर पिछले 3 दशक से शरणार्थी बने रहने को विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने तत्कालीन असम सरकार के साथ मिलकर फैसला लिया था कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को भारत की जमीन से निर्वासित किया जाएगा। इस फैसले के तहत ही अब तक सात बार एनआरसी ने नागरिकों की वैध सूची जारी करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल एनआरसी का विरोध करते रहे हैं।

बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा पट्टी है, जिस पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण गरीबी और भुखमरी के मारे बांग्लादेशी असम में घुसे चले आते हैं। क्योंकि यहां इन्हें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने-अपने वोट बैंक बनाने के लालच में भारतीय नागरिकता का सुगम आधार उपलब्ध करा देते हैं। मतदाता पहचान पत्र जहां इन्हें भारतीय नागरिकता का सम्मान हासिल करा देता है, वहीं राशन कार्ड की उपलब्धता इन्हें बीपीएल के दायरे में होने के कारण मुफ्त अनाज की सुविधा दिला देती हैं। आसानी से बन जाने वाले बहुउद्देश्यीय पहचान वाले आधार कार्ड भी इन घुसपैठियों ने बड़ी मात्रा में हासिल कर लिए हैं। इन सुविधाओं की आसान उपलब्धता के चलते देश में घुसपैठियों की तादाद चार करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है।

दरअसल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये शरणार्थी बने रहते, तब तक तो ठीक था, अलबत्ता भारतीय गुप्तचर संस्थाओं को जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्हें प्रोत्साहित कर भारत के विरुद्ध उकसा रही है। सऊदी अरब से धन की आमद इन्हें धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर आत्मघाती जिहादियों की नस्ल बनाने में लगी है। बांग्लादेश इन्हें हथियारों का जखीरा उपलब्ध करा रहा है। जाहिर है, ये जिहादी उपाय भारत के लिए किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं हैं। लिहाजा समय आ गया है कि जो आतंकवादी देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को सांगठनिक चुनौती के रूप में पेश आ रहे हैं, उन्हें देश से बेदखल किया जाए।

# किसान खेत न्याय यात्रा में सरकार पर बरसे जीतू पटवारी

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. इटारसी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान खेत न्याय यात्रा के तहत इटारसी जयस्तंभ चौक पर विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान जिले भर से आए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं किसान सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और यूरिया की कमी को लेकर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि खाद नहीं मिल पाने के कारण प्रदेश में अनेकों जगहों पर किसान भाई हैरान परेशान हो रहे हैं लेकिन सरकार को उनकी चिंता नहीं, आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नाला मोहल्ला निवासी गीता बाई को मृत घोषित कर दिए जाने के कारण वह लोकसभा चुनाव में वोट नही डाल पाई थी यह वोट चोरी का उदाहरण है जबकि गीता बाई ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाली थी तभी उन्होंने गीता बाई को मंच पर बुलाया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में विशाल आमसभा का आयोजन किया गया। जिसमें करीब पन्द्रह हजार से अधिक किसान कांग्रेस कार्यकर्ता आम नागरिक सभा एवं रैली में शामिल हुए। इस दौरान पुरानी इटारसी से आम सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान अनेक स्थानों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जगह-जगह पर भव्य स्वागत किया गया। आमसभा स्थल पर 50 से अधिक महिला एवं पुरुषों ने कांग्रेस की सदस्यता ली, वहीं जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं अबकी बार नगर पालिका सहित जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, मानक अग्रवाल, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा, संजय शर्मा, गिरजा शंकर शर्मा, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, पुष्पराज पटेल, रवि जायसवाल, मयूर जायसवाल, कन्हैया गोस्वामी सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

# समय पर पहचान से 80–90% बाल कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं : एम्स भोपाल

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। सितम्बर माह बाल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से बाल कैंसर जागरूकता वार्ता का आयोजन बाल चिकित्सा ओपीडी में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को बाल कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान, आधुनिक इलाज की उपलब्धता और बहुविषयक उपचार के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस चर्चा में डॉक्टरों, कैंसर से जूझ रहे बच्चों, उनके अभिभावकों और आसपास के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। डीएम पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी के रेजिडेंट्स डॉ. पक्कीरेश रेड्डी और डॉ. अनुराग मोहंती ने बाल कैंसर के प्रकारों पर जानकारी दी और बताया कि यदि समय पर पहचान और इलाज हो, तो 80–90% बाल कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। उन्होंने डॉक्टरों और आमजन में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। बाल रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा मलिक ने कैंसर उपचार में टीमवर्क की अहमियत समझाई। वहीं एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. बर्था रथिनम ने बच्चों के संपूर्ण उपचार की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक, डाइटिशियन और अन्य विशेषज्ञों का सहयोग शामिल है। कैनकिड्स संस्था की मदद से एम्स भोपाल बच्चों को "होम अवे फ्रॉम होम" आवासीय सुविधा, पोषण और अन्य सहायक सेवाएँ भी उपलब्ध करा रहा है। पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. वैशाली वाल्के ने शुरुआती जांच और एम्स भोपाल में उपलब्ध आधुनिक जांच सुविधाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अभिभावकों और बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए और नियमित व पूरा इलाज लेने के महत्व को बताया। अन्य विभागों से डॉ. प्रियंका (रेडियोथेरेपी) और डॉ. महेन्द्र (बाल शल्य चिकित्सा) ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया। पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नरेंद्र चौधरी ने सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की और कहा कि बहुविषयक उपचार से ही बच्चों को बेहतर इलाज और जीवन की आशा मिलती है। अंत में डॉ. योगेन्द्र यादव ने सभी नागरिकों से अपील की कि मध्य प्रदेश में बाल कैंसर संबंधी किसी भी जानकारी या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 8370001226 पर संपर्क करें।

# थाना टिमरनी में शांति समिति की बैठक संपन्न

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। आगामी नवरात्र एवं दशहरा पर्व को लेकर पुलिस थाना टिमरनी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के दुर्गा मंडलों के कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की रूपरेखा बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी संजीव कुमार नागू ने की। इस अवसर पर तहसीलदार श्वेता भमोरे थाना प्रभारी उदयराम सिंह चौहान, सीएमओ शेख अकबर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक एवं दुर्गा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एसडीओ नागू ने सभी समितियों से शासन के निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने नगर परिषद को पूरे नगर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने, मुख्य मार्गों पर पड़ी निर्माण सामग्री हटाने और विद्युत विभाग को पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए एक ओर का रास्ता खाली रखने पर जोर दिया। थाना प्रभारी उदयराम सिंह चौहान ने कहा कि सभी आयोजक शासन के नियमों के अनुरूप कार्य करें और आपसी सहयोग से त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराएं।बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनीत गीते सुनील दुबे राजा कौशल गिरीश घुरे, गुलशन चौरसिया पंकज तिवारी सुनील गौर विक्रम रघुवंशी दीपक शर्मा राजेन्द्र नागरे सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

# कैरियर कॉन्वेंट स्कूल के छात्र ऋषभ अवस्थी बने डिप्टी कलेक्टर

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी कलां: एमपीपीएससी की परीक्षा में मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बने ऋषभ अवस्थी का नगर में जगह-जगह स्वागत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान ऋषभ अवस्थी डिप्टी कलेक्टर की प्राथमिक शिक्षा कैरियर कान्वेंट स्कूल में पूरी हुई जहां उनके स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल के संचालक डॉ. अवनीश मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी विवेचना मिश्रा द्वारा ऋषभ अवस्थी का पुष्प माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने कहा कि यह देवरी नगर के लिए बड़े गौरव की बात है इसके पूर्व 40 साल पहले देवरी से एमपीपीएससी में चयनित होकर शशि कर्णावत डिप्टी कलेक्टर बनी थी और आज ऋषभ अवस्थी ने डिप्टी कलेक्टर में चयनित होकर नगर का गौरव बढ़ाया है और उनकी प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल से पूरी हुई है। इस दौरान स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए ऋषभ अवस्थी ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने आज के दिन का कभी सपना देखा था ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 साल

ही हुए हैं, मैंने 2005 से लेकर 2010 तक इस स्कूल में पढ़ाई की है और मैं भी ऐसी ग्रीन वाली ड्रेस पहन कर जैसे वह सामने बच्चे बैठे हैं ऐसे ही मैं भी बैठता था और मैंने उसे समय भी सपना देखा था और जब मैं पांचवीं कक्षा में इस स्कूल को छोड़कर गया था, उस समय भी सपना देखा था और मैंने सोचा था कि आज नहीं तो कल मैं सामने मंच के उस पार जरूर पहुंचूंगा। इस पूरी जर्नी में इस सपने पर पूरा विश्वास किया था कि एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं की खूब सपने देखो, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, खूब खाओ लेकिन विश्वास रखो कि वह सपना जरूर पूरा होगा। जब मैं सपना पूरा कर सकता हूं तो वह कोई भी कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि आप एग्जाम की तैयारी करो या डिप्टी कलेक्टर बनो आपको जो करना जो आपका मन कहे वह करो और पूरी निष्ठा के साथ करो, पूरे मन से करो और पूरा विश्वास रखो कि मैं उस चीज में जरूर सफल हो जाऊंगा। मैंने देखा है कि इंसान जीवन में जब भी अर्जुन का भाव करके कोई लक्ष्य साधता है तो उसमें कोई ना कोई कृष्णा जरूर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कुरुक्षेत्र पार कराता है ।मैंने यह कहानी बचपन में टीवी में देखी है। पड़ी तो आज तक नहीं है मैंने टीवी में देखा है जब-जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण से सहायता मांगी तब तब कृष्ण ने उनकी सहायता की है पर मैं हमेशा सोचता था कि आज श्री कृष्ण साक्षात मेरे सामने ना आए लेकिन मैं अर्जुन का भाव करके किसी से सहायता मांगूंगा तो सारा संसार मेरे लिए कृष्ण बन जाएगा और मेरी जर्नी में ऐसा हुआ भी। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऋषभ अवस्थी के पिता रमेश अवस्थी, रामकिशोर कूड़ेरिया, जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित विनीत पटेरिया, अनिल ढीमोले, संजय ब्रजपुरिया, दिनेश शुक्ला, राजेश दुबे, राजेश शर्मा सहित स्कूल के बच्चे और स्टाफ के लोग मौजूद रहे, संचालन अमित पाठक ने किया।

## कलम के सिपाही...

# सोमदत्त शास्त्री : व्यवहार में सरल, सहज, आत्मीय

चौड़ा माथा, खिचड़ी बाल, कभी सूट तो कभी सफारी पहने नजर आते थे वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री। व्यवहार में सरल, सहज, आत्मीय। मुस्कुराता चेहरा। मुँह में पान। चश्मा कभी आँखों तो कभी माथे पर दिखाई देता। हमेशा मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते। कलम के धनी। शब्द साधक। पेशे के लिए ईमानदार। शब्दचित्र खींचने में महारत। नए विषय गढ़ने का फन। भाषा हमेशा कलात्मक। सृजनात्मक पत्रकारिता के पक्षधर। रचनात्मक पत्रकारिता के हिमायती। समाजिक सरोकार से नाता। क्राइम रिपोर्टिंग में भी खूब लोहा मनवाया। उनकी एक पहचान छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति के जानकार के रूप में भी थी। शास्त्रीजी के साथ मेरे आत्मीय रिश्ते दैनिक भास्कर में साथ काम करते हुए कायम हुए। ये लगातार बने रहे। फोन करके एक-दूसरे की खैरियत पूछना, गर्मजोशी से मिलना उनकी खासियत थीं। कई अवसरों पर मैं उन्हें कामकाजी व्यस्तता में फोन करना भूलता तो उनका फोन पलटकर आता, फिर सुनने को मिलता कहां हो राजा..? मिलते नहीं हो? मैं उनसे माफी माँगता तो फौरन कहते... अरे राजा तुम तो संजीदा हो गए। नौकरी की परेशानियों और कामकाजी झमेले को मैं भी समझता हूँ। फुर्सत में था तो खैरियत मालूम करने फोन लगा दिया। चलो बस काम करो। फिर मिलते हैं। उनकी जीवटता की ये बड़ी मिसाल थी कि शायद दो या तीन साल से किडनी के फेल होने पर भी उनके चेहरे पर इसकी शिकन नहीं थीं। हँसते, गुदगुदाते फिर ठहाका लगाते। अच्छा लिखने पर बधाई देते।

अब बात उनकी खासियत की। राजनीतिक, सामाजिक विषयों के लेखन में महारत हासिल थी। फीचर, रिपोर्ताज और इण्टरव्यू का लहजा अलहदा होता। कई बार लेखन आतिशी होता तो कई अवसरों पर मखमली। अब बात पत्रकारिता के सफर की। इब्तिदा 1975 से हुई लेकिन खबरिया जगत में पहचान ब्लिट्ज में 40 साल पहले छपी नीलू हत्याकाण्ड की रपट से मिली थी। शुरुआती दौर में वे ब्लिट्ज, करंट, दिनमान, संडे मेल, प्रॉब इंडिया, मनोहर कहानियाँ, मनोरमा, सत्यकथा के लिए कलम चलाते रहे। 1984 में बिलासपुर से प्रकाशित लोक स्वर में सहायक सम्पादक के रूप में काम किया। कुछ माह प्रजाशक्ति में भी रहे। इसके बाद रीवा जागरण के प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1990 में काम किया। वर्ष 1993 में भोपाल दैनिक जागरण ज्वाइन कर लिया। अल्प समय में अपने काम के बूते पर वे पदोन्नत होकर प्रभारी संपादक बन गए। वर्ष 2002 में न्यूज एडिटर के रूप में भोपाल दैनिक भास्कर ज्वाइन किया। भास्कर में रहते हुए उन्होंने खबरों के कंटेट पर मुख्य रूप से काम किया। हैडिंग एवं डमी बनाने की उन्हें महारात हासिल थी। वे हमेशा अपने सहयोगियों का उत्साह वर्धन करते थे। इस कारण भास्कर में अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। चुनौतियों का सामना करने में वे कभी पीछे नहीं हटते। वर्ष 2005 में भास्कर छोड़ने के बाद उन्होंने जबलपुर भास्कर ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ वर्ष रहने के बाद बहुमत के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरु किया। वहीं डिजिटल युग को देखते हुए उन्होंने वर्ल्ड ब्यूरोक्रे ट पोर्टल शुरु किया। इस पोर्टल को लेकर वे काफी उत्साहित थे।

वे जीवन के अन्तिम दिनों में सिद्धान्ता अस्पताल में दाखिल थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अपने विद्या नगर स्थित निवास पर आ गए थे। वे खुद किडनी फेल होने की जानकारी से वाकिफ थे। डॉक्टरों ने वर्ष 2019 में किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। काफी कोशिशों के बाद भी उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट लड़खड़ाती सेहत के कारण नहीं हो सका।

अक्टूबर 2020 में कोरोना होने पर वे चिरायु अस्पताल में करीब 40 दिन तक दाखिल रहे। इस दौरान 25 दिन उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया लेकिन इच्छाशक्ति के धनी शास्त्रीजी स्वस्थ होकर घर लौट आए थे।

पत्रकारिता में सक्रिय हिस्सेदारी के कारण भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, माउण्ट आबू आदि में कई संगठनों ने उन्हें विभिन्न सम्मानों से नवाजा। इसकी चमक में वे कभी मगरूर नहीं रहे। वे मित्रों और सहयोगियों के बीच ठहाका लगाकर अपने सेहतमन्द होने का हमेशा सुबूत देते। आओ राजा उनका तकिया कलाम था। इस जुमले के बहाने संजीदा और बोझिल माहौल को खत्म करने का फन उन्हें आता था। राजनेताओं और अफसरों से नजदीकी रिश्ते होने का उन्हें कभी घमण्ड नहीं रहा। अब वे नहीं है, सिर्फ यादें हैं। **-अलीम बजमी**

# जब जंगल कटेंगे तो जानवर गांव शहर की ओर आएंगे

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

बिजनौर से मुरादाबाद तक तेंदुओं, भेड़ियों और गुलदार का खौफ है। ये आदमखोर तेंदुए मुरादाबाद में डर का माहौल बनाए हुए हैं। तेंदुए से डर कर ग्रामीण अपनी खेतों पर नहीं जा रहे हैं। वहीं बिजनौर में गुलदार खौफ का दूसरा नाम बन गया है। गुलदार दो बच्चों को घर से खींच कर ले गया। बहराइच में भेड़िया का खौफ है। यहां भी भेड़िया ने एक पांच साल की बच्ची को घर से उठाकर ले गया और पूरी तरह नोचकर मार डाला डाला। लखीमपुर खेरी, सीतापुर में भी बाघ और तेंदुए का आतंक है। उत्तर प्रदेश में भेड़िया या दूसरे जंगली जानवरों के हमले की कहानी नई नहीं है। पिछले साल भी बहराइच में भेड़िया का आतंक था। 1996 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में भेड़ियों ने 30 बच्चों को मारा था। जयपुर में पिछले हफ़्ते रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया था। जब जानवर अपने घरों से विस्थापित होते हैं, तो वे हमारी बनाई दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए भटकते हैं। हमने उनकी जमीन छीन ली और अब वे हमारी बनाई हुई दुनिया में जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय शहरों और कस्बों में एक नया दृश्य सामने आया है। वन्यजीवों का आवास जंगलों से सिमटता जा रहा है और परिणामस्वरूप वे मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह तेंदुओं का शहरी क्षेत्रों में दिखना हो, हाथियों का गाँवों में प्रवेश, या फिर बंदरों का खुले बाजारों में उत्पात मचाना, हर ओर वन्यजीवों का अस्तित्व संकट में है। यह समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। वन्यजीवों का मानव बस्तियों की ओर आना कोई नई घटना नहीं है। आदिकाल से मानव और प्रकृति के बीच एक सह-अस्तित्व का रिश्ता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह संतुलन बिगड़ गया है। जहाँ पहले जंगल घने और विशाल थे, आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि विस्तार के चलते जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। परिणामस्वरूप, वन्यजीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और उनके पास अपने जीवन को जारी रखने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। इसी कारण वे भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। वन्यजीवों का यह विस्थापन सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। जब तेंदुआ या हाथी गाँवों में प्रवेश करता है, तो न केवल उनके द्वारा जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि उन जानवरों के लिए भी यह अनुकूल नहीं होता। मनुष्यों द्वारा किया गया हमला और भय का सामना करने के बाद वे और आक्रामक हो जाते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है। वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष का एक बड़ा सामाजिक पहलू है। जंगलों के कटने से वनवासियों और ग्रामीणों की जीवनशैली पर गहरा असर पड़ता है। बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों पर ही निर्भर करते हैं- चाहे वह जल, जंगल, जमीन से जुड़ा उनका अधिकार हो या फिर उनकी परंपरागत जीवनशैली। जंगलों की कटाई के चलते न केवल वन्यजीवों का घर छिन रहा है, बल्कि इन समुदायों की आजीविका भी खतरे में आ रही है। जंगलों के विनाश से जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी प्रजातियाँ- वनस्पति, जीव-जंतु, पक्षी- अपनी प्राकृतिक जगहों पर रहें। जब हम जंगलों को काटते हैं, तो हम उस संतुलन को नष्ट कर देते हैं जो हजारों सालों से प्रकृति ने खुद बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, पारिस्थितिकी तंत्र की श्रृंखला टूट जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का चक्र बिगड़ जाता है।

भारत में जंगलों की कटाई की दर चिंताजनक है। वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में हजारों हेक्टेयर जंगलों को नष्ट किया गया है। यह कटाई मुख्यतः औद्योगिकीकरण, कृषि के विस्तार और नगरीकरण के कारण हो रही है। जहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब बड़े-बड़े शहर और फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं। सरकार की नीतियाँ भी कई बार इस समस्या को बढ़ावा देती हैं। विकास की आड़ में वन क्षेत्रों को उद्योगों और बस्तियों के लिए खोल दिया जाता है, जिससे वन्य जीवों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। जब जंगल कटते हैं, तो जानवरों के पास न तो भोजन होता है और न ही पानी। जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण वे इंसानी बस्तियों की ओर जाने को मजबूर हो जाते हैं। तेंदुओं का गांवों में आकर मवेशियों का शिकार करना, हाथियों का खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट करना और यहाँ तक कि कुत्तों और बंदरों का शहरी इलाकों में आकर भोजन की तलाश करना, यह सभी संकेत हैं कि हमने उनके प्राकृतिक आवासों को छीन लिया है। शहरी क्षेत्रों में यह टकराव न केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ तेंदुओं के हमलों में लोग घायल हुए हैं, और कई बार इन संघर्षों में वन्यजीवों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जंगलों की कटाई का एक अन्य गंभीर परिणाम जलवायु परिवर्तन है। पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमारी वायु शुद्ध होती है। जब हम जंगलों को काटते हैं, तो हम इस प्राकृतिक प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। इसके अलावा, जंगलों की कटाई से बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ अधिक होने लगी हैं।

अब सवाल यह उठता है कि इस संकट का समाधान क्या हो सकता है? समाधान कई स्तरों पर संभव है- सरकारी नीतियों से लेकर जन-जागरूकता तक। सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि जंगलों का संरक्षण केवल वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। अगर हम जंगलों को नष्ट करते रहे, तो आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को जंगलों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। औद्योगिक और शहरी विकास की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वनों की सुरक्षा और पुनर्वनीकरण (reforestation) की योजनाओं को अधिक महत्व देना होगा। इसके अलावा, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार देने की आवश्यकता है ताकि जानवरों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सके।

सामाजिक स्तर पर, हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। वन्यजीवों को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानने के बजाय, हमें उन्हें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा समझना होगा। जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि जंगल और वन्यजीव हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीनकाल से ही मानव और वन्यजीवों के बीच एक संतुलित सह-अस्तित्व रहा है। यह सह-अस्तित्व आज भी संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी नीतियों और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर हम जंगलों की कटाई रोकने में सफल होते हैं, तो वन्यजीवों को अपने प्राकृतिक आवास में बने रहने का अवसर मिलेगा और मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष कम होगा।

यह सही समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और संतुलित भविष्य की नींव रखें। यदि हम आज कदम नहीं उठाते, तो जंगलों और वन्यजीवों का यह संकट न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लगाएगा। जंगलों का संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा अब केवल वन विभाग का काम नहीं रह गया है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। समाधान की दिशा में पहला कदम यही होगा कि हम जंगलों को नष्ट होने से बचाएँ और वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी आवास सुनिश्चित करें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
**RNI-MPBIL/2011/39805** समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)